जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए विशेष भर्ती करनी चाहिए। आरक्षित पदों पर अन्य आम उम्मीदवारों को भर्ती नहीं की जानी चाहिये; तथा

(ii) अनुसूचित जाति।अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को वांछित स्तर तक लाने के लिए, बैंकों को केवल अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का प्रबन्ध करना चाहिये। यदि आवश्यक हो तो योग्य अ०जा०/अ०ज० जाति के उम्मीदवारों के बैंकों को उनके चयन के बाद अधिक लम्बी अवधि के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करने चाहियें।

Utilisation of Foreign Exchange Reserves

659. SHRI C. N. VISVANATHAN: Will the DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE be pleased to state:

(a) the amount of foreign exchange reserves of our country;

(b) the precise modality in which such reserves have been used positively for our developmental efforts; and

(c) whether it is a fact that non-utilisation of such reserves to the optimum extent has resulted in a gain to the foreign countries at a very high price for lack of a dynamic policy?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGRAWAL): (a) India's foreign exchange reserves (excluding gold and Special Drawing Rights) amounted to Rs. 5141.51 crores as on 9th February, 1979.

(b) A series of measures have been taken by the Government to utilise the foreign exchange reserves fruitfully with a view to enhance the rate of growth of the economy and to maintain reasonable price stability. These include:

(i) Import policy has been progressively liberalised and relevant procedures simplified with a view to improving utilisation of existing and establishment of new industrial capacity while taking care that indigenous industry is not hurt. Actual users (a major category of licencees) are now entitled to automatic licences for import of industrial raw materials, components spares parts (except restricted and banned items) within liberal limits. The Open General Licence list has been substantially expanded to include, among others, leather machinery, garment and hosiery machinery and a wide range of machine tools. Provision has been made for imports on a global basis of capital goods and machinery for 14 specified priority industries to remove bottlenecks in speedy completion of projects. Canalising agencies are being provided foreign exchange on a liberal scale to enable them to service the needs of their clients for imported canalised items.

(ii) Increased plan outlays and a general step up in demand have resulted in enhanced requirements for important commodities like steel, cement, cotton, fertiliser and fertiliser raw materials, non-ferrous metals, etc. Foreign exchange reserves have been liberally utilised to augment domestic supply of these inputs and this has helped maintain the tempo of development.

(iii) A special facility has been established to enable intending importers of capital goods to obtain, on reasonable terms, rupee funds with which they can purchase the requisite foreign exchange.

(iv) Price stability is an important condition for sustained economic growth. Government has, therefore, been importing consumer commodities which are in short supply in the domestic market such as edible oils.

While it is too early to estimate accurately the amount of foreign exchange likely to be spent as a result of the above measures, the provisional value of imports during April-November, 1978 is Rs. 4121.02

crores as compared to Rs. 3400.11 crores in the same period last year.

(c) No, Sir. Utilisation of foreign exchange reserves has to be necessarily considered in the medium term perspective. A series of steps as above have been taken by the Government to utilise the foreign exchange reserves productively and in keeping with our overall plan objective of sustained growth with price stability.

Our foreign exchange reserves are not very large keeping in view the sizeable impact which adverse monsoon conditions can have on our agricultural and food production, lack of secondary line of reserves, substantial increases in the price of crude oil and industrial imports, and the protectionist environment and recessionary trends in the developed countries which can lead to slowing down of exports. A comfortable level of foreign exchange reserves is necessary for imparting stability to our development and import policies.

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की ओर बकाया कर

660. **श्री हुकमदेव नारायण यादव :** क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन कौन सी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के विरुद्ध कितने-कितने कर बकाया हैं तथा इस राशि की वसूली के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का अधिग्रहण करने का है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार उस राशि को कम करने का है जो इन कम्पनियों द्वारा विदेशों को भेजी जाती है ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार-उल्लाह) : (क) "बहुराष्ट्रीय कम्पनी" पद की कोई मान्य परिभाषा नहीं है। इसलिए इस प्रश्न के प्रयोजनों के लिए विदेशी कम्पनियों की उन शाखाओं/सहायक कम्पनियों के सम्बन्ध में सूचना दी जा रही है जो भारत में चलाई जा रही हैं। जिन विदेशी कम्पनियों की शाखाओं/सहायक कम्पनियों की तरफ 31-3-1978 को प्रत्यक्ष करों की बकाया थी, उनके सम्पर्क में इस समय उपलब्ध सूचना का एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये पत्र संख्या LT—3332/79]

जिन मामलों में करों की बकाया होती है, उनमें प्रत्येक मामले की वस्तुस्थिति पर निर्भर करते हुए इन करों की बकाया को वसूल करने/कम करने के लिए आय कर अधिनियम के अधीन किए गए विभिन्न उपाय सम्बन्धित आयकर प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर किए जाते हैं।

(ख) और (ग). विदेशी कम्पनियों के कार्यों के सम्बन्ध में सरकार की नीति औद्योगिक नीति सम्बन्धी विवरण-पत्र में निहित है जो 23-12-77 को सदन-पटल पर रखा गया था। इस विवरण पत्र के पैराग्राफ 24 से 26 में इसका उल्लेख मिलेगा। विदेशी कम्पनियों को इस देश में कार्य करने की इजाजत दी जायगी बशर्ते कि वे विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबंधों का पालन करें। सभी अनुमोदित विदेशी निवेश के लिए चालू तथा पूंजीगत मदों को स्वदेश भेजने की सुविधाएं दी जाती हैं।

एक गैर-सरकारी पार्टी द्वारा खजुराहो पयटन केन्द्र में एक होटल का निर्माण

661. **श्री लक्ष्मी नारायण नायक :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक गैर-सरकारी पार्टी द्वारा खजुराहो पर्यटन केन्द्र में 46 कमरों के एक होटल के निर्माण की मंजूरी दी है और क्या उसका निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है और यदि नहीं, तो उसका निर्माण कार्य कब प्रारम्भ होगा; और

(ख) देश में उन पर्यटक केन्द्रों के नाम क्या हैं जहां पर कार्यालय इमारतों तथा कर्मचारी क्वार्टरों की व्यवस्था केन्द्र सरकार द्वारा कर दी गयी है और क्या सरकार खजुराहो में भी कार्यालय इमारतें तथा कर्मचारी क्वार्टरों की व्यवस्था करेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक): (क) जी हां। सरकार ने खजुराहो में एक गैर-सरकारी पार्टी द्वारा 46 कमरों के एक होटल का निर्माण अनुमोदित किया है। कार्य प्रारम्भ हो गया है।

(ख) सरकार ने विशेषरूप से पर्यटन विभाग के लिए किन्हीं कार्यालय इमारतों या स्टाफ-क्वार्टरों का निर्माण नहीं किया है। पर्यटक कार्यालयों की हाउसिंग के लिए आफिस प्रैमिसेज किराए पर लिए गए हैं। रैजीडेन्शल क्वार्टरों के लिए, स्टाफ केन्द्रीय सरकार के सामान्य पूल आवास (जनरल पूल एकोमोडेशन) पर निर्भर रहता है। यदि उन्हें ऐसा आवास आबंटित नहीं किया जाता तो वे वित्त मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी किए गए आदेशों के अधीन मकान किराया भत्ता लेते हैं। खजुराहो में नियुक्त स्टाफ के लिए इन आदेशों के अधीन कोई मकान किराया भत्ता स्वीकार्य नहीं है। खजुराहो आफिस प्रैमिसेज राज्य सरकार से किराए परलिया गया है। इस समय खजुराहो में एक कार्यालय इमारत या स्टाफ-क्वार्टरों के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।